



आत्मनिर्भर भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान

मिथिलेश तिवारी, प्रियंका सिंह, दिलीप कुमार एवं अखिलेश कुमार सिंह

भा.कु.अनु.प.— भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

संवादी लेखक का ई-मेल: Mithilesh.Tiwari@icar.gov.in

वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत, दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ था। इसका प्रमुख कारण देश के ग्रामीण बाजार की जोरदार शक्ति ही माना गया था। अब कोविड-19 के बाद भी एकबार फिर भारत के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहमियत दिखाई दे रही है।

सरकार ने कोविड-19 के संकट से चरमराती देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कहा गया है कि नए आर्थिक पैकेज में ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मछले उद्यमों, किसानों और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों पर खास ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस पैकेज में देश के लिए आत्मनिर्भरता के पाँच स्तंभों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें तेजी से छलांग लगाती अर्थव्यवस्था, आधुनिक भारत की पहचान बनता बुनियादी ढांचा, नए जमाने की तकनीक केंद्रित व्यवस्थाओं पर चलता तंत्र, देश की ताकत बन रही आबादी और मांग एवं आपूर्ति चक्र को मजबूत बनाना शामिल है। निसंदेह नया पैकेज न केवल अर्थव्यवस्था को गतिशील करेगा, वरन् देश को आत्मनिर्भरता की नई डगर पर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में देश की आत्मनिर्भरता ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देगी। इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक अध्ययन रिपोर्टों में भी यह बात उभरकर सामने आ रही है कि कोविड-19 भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे कम असर गिरेगा और कोविड-19 के बाद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि कोरोना वायरस की चुनौतियों के कारण भारत की विकास दर में तेज गिरावट आएगी लेकिन प्रचुर खाद्यान्न भंडार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के लिए सहारा होंगे और इन आधारों से भारत कोविड-19 के बाद तेजी से आगे बढ़ सकेगा। एशियाई विकास बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के पास कृषि और खाद्यान्न जैसे मजबूत आर्थिक बुनियादी घटक है

जिनकी ताकत से भारत अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जोरदार आर्थिक वृद्धि करते हुए दिखाई दे सकेगा।

हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान करीब 17 फीसदी है। लेकिन देश के 60 फीसदी लोग खेती पर आश्रित हैं और वे बहुत कुछ आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है और शेष 50 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत छोटे-मछले उद्योग और सेवाक्षेत्र का योगदान है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस समय कोविड-19 के बीच भारत का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि देश के सामने 135 करोड़ लोगों को भोजन संबंधी चिंता नहीं है। नवीनतम स्थिति के अनुसार अप्रैल 2020 के अंत तक देश के पास करीब 10 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार सुनिश्चित हो गया है। जिससे करीब डेढ़ वर्ष तक देश के लोगों की खाद्यान्न जरूरतों को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।

इतना ही नहीं कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत फसल वर्ष 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़े सुकुन का संकेत दे रहे हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 29.12 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकता है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के 3.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की बात कहीं गई है। यह भी बताया गया है कि आगामी फसल वर्ष 2020-21 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 29.83 करोड़ टन रखा गया है देश में पहली बार इतना बड़ा खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है। निसंदेह भारतीय मौसम विज्ञान की अच्छे मानसून की यह संभावना न केवल देश के कृषि जगत के लिए अपितु पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है।

सरकार ने किसानों की उनकी उपज मंडियों के अलावा सीधे भी बेचने की इजाजत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पशुपालन और डेयरी उत्पादन को विशेष अहमियत दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के सबसे बड़े स्रोत मनरेगा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही अधिक लोगों को रोजगार मिल सके इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की मौजूद



सिंचाई और जल संरक्षण योजनाओं को भी मनरेगा से जोड़ दिया गया है। लॉकडाउन के बीच भी घातापूर्वक खेती और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधियों को शुरू किए जाने से उर्वरक, बीज, कृषि रसायन जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां और ट्रैक्टर निर्माताओं को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। कृषि गतिविधियों में दी गई राहत से उपभोग की मांग बढ़ गई है। ऐसे में अब ग्रामीण भारत सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को गतिशील करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है।

अच्छे मूल्यों पर फसल खरीदे जाने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय बढ़ाने के प्रयास से ग्रामीणों को आगे बढ़ाएंगे। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो मजदूर वापस अपने गांव आए हैं वे अब जल्दी शहर जाने वाले नहीं हैं। वे कम से कम आगामी तीन-चार महीनों तक गांव में ही रहेंगे और कृषि कार्य करेंगे। इससे खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की मांग बढ़ेगी। इसी तरह सरकार के द्वारा लोगों के जनधन खाते में नकद पैसा डालने जैसे प्रयासों से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

कोविड-16 में कृषि सुधारों का भी एक अवसर छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस के फैलने के कारण देश में खेती करने के परम्परागत तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। फसलों की बुआई, कटाई, और भंडारण के तरीकों में जो परिवर्तन आया है उसके कारण किसानों के द्वारा खेत तैयार करने, खेत में बुआई और फसल कटाई के काम में मशीनों का अधिक प्रयोग, सरकार के द्वारा गोदामों एवं शीतगृहों को बाजार का दर्जा दिया जाना, निजी

मंडियां खोलने को प्रोत्साहनदायक अनुभूति, कृषक उत्पादन संगठनों को मंडी की सीमा में बाहर लेने-देने की अनुमति, श्रम बचाने वाले उपकरणों के कारण कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण, फसल विविधीकरण जैसे कृषि सुधार दिखाई दे रहे हैं।

बाजार में आ रही रबी की फसल के मार्केटिंग के लिए मौजूदा मंडी खरीद प्रणाली से आगे बढ़कर सभी मार्केटिंग चैनल खोलने की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, ताकि सीधे किसान से खरीद भी हो सके। गाँवों में मनरेगा को पूरी तरह कारगर ढंग से लागू किया जाए। साथ ही मजदूरी के लंबित भुगतान एवं काम मांगने पर काम दिलाने जैसी समस्याओं का भी समाधान निकाला जाए। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा किसानों के समक्ष खरीफ फसल आने से पहले कृषि उत्पादन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए नकदी का संकट नहीं आए।

कोविड-19 के संकट से देश को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रूपए का व्यापक आर्थिक पैकेज न केवल देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने से बचाएगा, वरना ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर देश को आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ाएगा। हम उम्मीद करें कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच नया आर्थिक पैकेज भारत में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, बेहतर कृषि, प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, डेयरी उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे खाद्य पदार्थों पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को नया प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। जिससे मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बनते हुए दिखाई दे सकेंगी।

